भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 119
उत्तर देने की तारीख 25.07.2022

शिक्षा की गुणवत्ता

***119 श्री राहुल कस्वां:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्राथमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा की गुणवत्ता कम होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विद्यार्थियों के नामांकन की हाल ही में समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार देश में कंप्यूटर और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में प्राथमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

'शिक्षा की गुणवत्ता' के संबंध में श्री राहुल कस्वां, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): शिक्षा का स्तर एक व्यापक शब्द है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया, सीखने का माहौल, पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, अधिगम परिणाम, मूल्यांकन आदि शामिल हैं। समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन, अनुकूल अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए सहायता, आईसीटी और डिजिटल पहल, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, पढ़े भारत बढ़े भारत के लिए सहायता, आदि जैसी विभिन्न पहलों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की चक्र अवधि के साथ कक्षा III, V, VIII और X पर केन्द्रित नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। एनएएस का अंतिम दौर 12 नवंम्बर, 2021 को पूरे भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्र शामिल थे। एनएएस का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की स्थिति के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना है, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। एनएएस 2021 के लिए राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिलों की रिपोर्टें 25.05.2022 को प्रकाशित की गई हैं और यह http://nas.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख): यूडाइस+ डाटा के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान देश भर के सभी प्रबंधन स्कूलों में छात्रों का कुल नामांकन 253804461 था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 178684204 छात्र शामिल थे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो और देश में स्कूल शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने 07 जनवरी, 2021 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दिशानिर्देश साझा किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 6-18 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करना, नामांकन अभियान और जागरूकता पैदा करना, स्कूलों के बंद होने के दौरान छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) के लिए निरंतर शिक्षा, स्कूल को फिर से खोलने पर छात्र सहायता और शिक्षक क्षमता निर्माण शामिल हैं। दिशानिर्देशों का लिंक https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/guidelines_oosc.pdf है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों सहित प्रत्येक छात्र हेतु निरंतर शिक्षा तक पहुंच मिले स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।आत्म निर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल 17 मई, 2020 को शुरू की गई है, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित शिक्षा तक विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से पहुँच को सक्षम बनाने के लिए सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पहल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- दीक्षा-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा: और सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोड सक्रिय पाठ्यपुस्तकें।
- कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक चिन्हित स्वयं प्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)

- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट - शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग
- दृष्टिबाधित और श्रव्य बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डीएआईएसवाई) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित विशेष ई-कंटेंट

जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल डिवाइस/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, शिक्षार्थियों के आवास पर आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकें एवं वर्कशीट, और समुदाय/मोहल्ला कक्षाएं आयोजित करने जैसी कई पहल की हैं। विभाग की नवाचार निधि का उपयोग स्कूलों में मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने के लिए किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सतत अधिगम योजना (सीएलपी) शुरू की गई है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कठिन होता है, वहाँ प्री-लोडेड टैबलेट का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है।

'डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट,2021' तैयार की गई है जिसमें देश भर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल और दूरस्थ अधिगम पहलों को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट का लिंक https://www.education.gov.in/sites/upload_riles/mhrd/flies/irde_21.pdf. है।

साथ ही, समग्र शिक्षा को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों में आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी घटक में बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अधीन छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। अब तक 120614 स्कूलों में आईसीटी लैब और 82120 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम को मंजूरी दी जा चुकी है।

(घ): देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

1. समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना और पीएम पोषण को एनईपी 2020 की सिफारिश के साथ जोड़ा गया है। समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा में विभिन्न पहलों जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपलब्धि सर्वेक्षण के संचालन, अनुकूल अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, आदि के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना / उनका सुदृढीकरण , स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन और संचालन, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना शामिल है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से कक्षा–3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त कर ले, समग्र शिक्षा के तहत समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुन भारत) शुरू की गई है और इसके लिए ई–सामग्री दीक्षा DIKSHA प्लेटफॉर्म में जारी की गई है।

3. शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों / प्रधानाचार्यों और अन्य हितधारकों के लिए स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0 और 3.0 एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

4. माध्यमिक स्तर के अधिगम परिणामों को अधिसूचित कर दिया गया है।

5. विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए उचित कदम उठाने के लिए शिक्षा प्रणाली की कार्यशीलता के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 नवंबर, 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 आयोजित किया गया है।

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड देने के लिए एक 70 संकेतक आधारित मैट्रिक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) विकसित किया गया है। जिला स्तरीय प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) तैयार किया गया है और पीजीआई–जिला के संकलन के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

7. सीबीएसई द्वारा सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 3, 5, व 8 के लिए प्रतिस्पर्धा आधारित आकलन के लिए स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग लेवल (सफल) फ्रेमवर्क विकसित किया गया व 29.07.2021 को शुरू किया गया जिसमें मूल अवधारणाओं की जांच, एप्लीकेशन आधारित प्रश्नों और उच्च स्तरीय विचार कौशल पर फोकस किया गया है।

8. विद्या प्रवेश– 29 जुलाई, 2021 को कक्षा–I के बच्चों के लिए तीन माह के प्ले–आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे जब अपनी ग्रेड–I की कक्षा में आएं तो उन्हें एक हंसता–खेलता और प्यार भरा वातावरण मिले।

*****